VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(26 March 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- **रूस-यूक्रेन 'काला सागर सुरक्षा समझौते' में क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?**
- **अमेरिका में युद्ध योजना के लीक मुद्दे से जुड़ा सिग्नल मैसेजिंग ऐप क्या है?**
- **पर्यावरण मंत्रालय ने 2024-25 में प्रदूषण नियंत्रण कोष के 858 करोड़ रुपये का 1% से भी कम खर्च किया**
- **MCQ**

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

रूस-यूक्रेन काला सागर सुरक्षा समझौते में क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?

चर्चा में क्यों है?

- रूस और यूक्रेन ने 25 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में वार्ता के बाद काला सागर और ऊर्जा अवसंरचना पर सैन्य हमलों को रोकने के लिए एक समझौता किया है। सऊदी की राजधानी रियाद में तीन दिनों तक चली वार्ता एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास है।
- रूस ने 25 मार्च को कहा कि अमेरिका ने काला सागर में समुद्री सुरक्षा समझौते पर सहमति जताने के बदले में खाद्य, उर्वरक और शिपिंग कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने में उसकी मदद करने पर सहमति जताई है।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने घोषणा की कि दोनों राष्ट्र "काला सागर में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने, बल के उपयोग को खत्म करने और काला सागर में सैन्य उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक जहाजों के उपयोग को रोकने के लिए सहमत

हुए हैं"। साथ ही इस समझौते में यूक्रेन और रूस में ऊर्जा स्थलों को लक्षित करने वाले हमलों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास भी शामिल हैं।

काला सागर युद्ध विराम समझौते में क्या है?

- अमेरिका और रूस ने काला सागर में सुरक्षित नौवहन पर सहमति जताई है, जो वार्ता का मुख्य केंद्र रहा है। इसके अतिरिक्त, वे रूस और यूक्रेन में ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों पर प्रतिबंध लगाने के उपायों पर मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए।
- अमेरिका कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए वैश्विक बाजारों तक रूस की पहुंच को बहाल करने में भी मदद करेगा - हालांकि इस स्तर पर रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों का क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं है।
- अमेरिका ने यह भी कहा कि वह इस बात पर सहमत है कि वह जबरन स्थानांतरित किए गए यूक्रेनी बच्चों को वापस करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
- यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने समझौते की पुष्टि की, लेकिन कहा कि यूक्रेनी सरकार का कहना है कि काला सागर के पूर्वी हिस्से के बाहर रूसी सैन्य जहाजों की कोई भी गतिविधि इस समझौते की भावना का उल्लंघन होगी।

- रूस ने यह पुष्टि की है कि वह युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है, लेकिन समय और शर्तों को लेकर असहमति है।
- हालांकि वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मानना है कि युद्ध विराम अमेरिकी घोषणा के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन रूस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह तभी लागू होगा जब खाद्य और उर्वरक निर्यात में शामिल कंपनियों के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।

यह समझौता वास्तव में 'काला सागर पहल' की ओर वापसी है:

- यह समझौता रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाल के दिनों में रियाद में काला सागर पर केंद्रित वार्ता के बीच हुआ है। लेकिन वार्ता का आधार वहाँ शिपिंग को सुरक्षित करने का एक सौदा था जो 18 महीने से अधिक समय पहले विफल हो गया था।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित उस समझौते पर जुलाई 2022 में तुर्की, संयुक्त राष्ट्र और रूस के बीच बातचीत हुई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूक्रेन अपने दक्षिणी बंदरगाहों के ज़रिए बिना किसी हमले के अनाज का निर्यात जारी रख सके। इसे 'काला सागर अनाज पहल' के रूप में जाना जाता था।

- उस समझौते से रूस को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसने रूसी कृषि निर्यात को भी बढ़ाया - लेकिन जुलाई 2023 में रूस ने इस पहल से हाथ खींच लिया, क्योंकि उसने पश्चिम पर समझौते के इस हिस्से से मुकरने का आरोप लगाया। इसका मतलब यह हुआ कि रूस ने यूक्रेन से आने-जाने वाले मालवाहक जहाजों को सुरक्षित मार्ग देना बंद कर दिया और इसके बाद देश के अनाज निर्यात में गिरावट आई।

इस समझौते में रूस को क्या मिलेगा?

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि यह समझौता कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए विश्व बाजार में रूस की पहुंच को बहाल करने, समुद्री बीमा लागत को कम करने और ऐसे लेनदेन के लिए बंदरगाहों और भुगतान प्रणालियों तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा।
- साथ ही इसमें रुसी राज्य के कृषि बैंक रॉसेलखोजबैंक "और खाद्य (मछली उत्पादों सहित) और उर्वरकों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने में शामिल अन्य वित्तीय संगठनों, स्विफ्ट से उनके संबंध और आवश्यक संवाददाता खातों के खुलने पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। अन्य शर्तों में बंदरगाहों में जहाजों के रखरखाव पर

प्रतिबंध हटाना और खाद्य और उर्वरक व्यापार में शामिल रूसी ध्वज वाले जहाजों के खिलाफ प्रतिबंध हटाना शामिल है।

- रूस को कृषि मशीनरी की आपूर्ति पर प्रतिबंध भी हटा दिए जाएंगे, साथ ही खाद्य (मछली उत्पादों सहित) और उर्वरकों के उत्पादन में शामिल अन्य वस्तुओं पर भी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे।

इस समझौते से यूक्रेन को क्या मिलेगा?

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह यूक्रेन के साथ सहमत है कि "युद्धबंदियों के आदान-प्रदान, नागरिक बंदियों की रिहाई और जबरन स्थानांतरित किए गए यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबद्ध है"।

अमेरिका में युद्ध योजना के लीक मुद्दे से जुड़ा सिग्नल मैसेजिंग ऐप क्या है?

मामला क्या है?

- हाल ही में एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप 'सिग्नल' ने दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जब अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के शीर्ष व्यक्तियों; रक्षा सचिव पीट हेगसेग और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित ने कथित तौर पर इस सेवा का उपयोग अत्यधिक संवेदनशील सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए किया, जबकि अनजाने में चैट में अटलांटिक पत्रिका के प्रधान संपादक जेफरी गोल्डबर्ग भी शामिल हो गए।
- 25 मार्च को, गोल्डबर्ग ने अटलांटिक में एक लेख प्रकाशित किया कि कैसे उन्हें इस महीने की शुरुआत में सिग्नल पर 18 लोगों की चैट में जोड़ा गया था, जिसमें यमन में सैन्य हमलों पर चर्चा की गई थी।

- उल्लेखनीय है कि संवेदनशील सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए सिग्नल का उपयोग ऐप के बारे में कुछ सवाल उठा रहा है, जिसमें हैकर्स और अन्य बुरे लोगों के खिलाफ इसकी सुरक्षा का स्तर भी शामिल है।

सिग्नल ऐप क्या है?

- सिग्नल टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए एक एन्क्रिप्टेड सेवा है, लेकिन यह फोन और वीडियो कॉल को भी संभाल सकता है, जिससे यह दूसरों के साथ सुरक्षित चैनल पर बात करने के लिए एक बहुमुखी ऐप बन जाता है। इसके एक समूह चैट में 1,000 लोग शामिल हो सकते हैं, और संदेशों को कुछ समय के बाद गायब होने के लिए सेट किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि सिग्नल के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के कारण उपयोगकर्ताओं इससे जुड़ रहे है। इसका एन्क्रिप्शन किसी तीसरे पक्ष को बातचीत की सामग्री देखने या कॉल सुनने से रोकता है। दूसरे शब्दों में, सिग्नल पर भेजे गए संदेश और कॉल को उलझा या तोड़मरोड़ दिया जाता है और केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पास ही उन्हें समझने की कुंजी होती है। सिग्नल यह भी कहता है कि यह कोई संवेदनशील जानकारी एकत्र या संग्रहीत नहीं करता है।

- एक अन्य लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप, टेलीग्राम के विपरीत, सिग्नल पर एन्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट रूप से चालू होता है।

सिग्नल ऐप का इस्तेमाल आम तौर पर किस लिए किया जाता है?

- इसके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की वजह से, सिग्नल का इस्तेमाल अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया पेशेवरों के साथ-साथ सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों द्वारा किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सरकार के अधिकारियों द्वारा संवेदनशील बैठकों को शेड्यूल करने जैसे संगठनात्मक पत्राचार के लिए सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन बिडेन प्रशासन में, जिन लोगों को अपने व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए फ़ोन पर इसे डाउनलोड करने की अनुमति थी, उन्हें ऐप का संयम से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया था। 2017 में, अमेरिकी सीनेट सार्जेंट एट आर्म्स ने सीनेट कर्मचारियों के लिए सिग्नल के उपयोग को मंजूरी दी।
- एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि विभिन्न एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप अमेरिका में सरकारी अधिकारियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
- रॉयटर्स ने सिग्नल को उन उपकरणों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है जिसका उपयोग टिपस्टर अपने पत्रकारों के साथ गोपनीय समाचार सुझावों को साझा करने के लिए कर सकते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

क्या सिग्नल ऐप को हैक किया जा सकता है?

- यद्यपि सिग्नल ऐप अपनी सेवा की गोपनीयता का दावा करता है, और विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि यह पारंपरिक टेक्स्टिंग से ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि इसे हैक किया जा सकता है। और फरवरी 2025 में, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने कर्मचारियों को सिग्नल ऐप में कमज़ोरियों के बारे में चेतावनी देते हुए एक ऑपरेशनल सिक्योरिटी स्पेशल बुलेटिन भेजा।
- सिग्नल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बुलेटिन का जवाब देते हुए कहा कि NSA के "मेमो में सिग्नल के संबंध में 'कमज़ोरी' शब्द का इस्तेमाल किया गया था-लेकिन इसका सिग्नल की मुख्य तकनीक से कोई लेना-देना नहीं था।

क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा सिग्नल का उपयोग करने में कोई कानूनी समस्या है?

- अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि संभवतः हाँ। सिग्नल पर संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा विवरण साझा करना जासूसी अधिनियम का उल्लंघन हो सकता है।

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा कि "मुझे सिग्नल के बारे में कुछ भी नहीं पता"। हालांकि राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि सिग्नल "नंबर 1 डिवाइस या ऐप है जिसका उपयोग किया जाता है" और उन्होंने NSA वाल्ट्ज से सरकारी अधिकारियों द्वारा इसके उपयोग का पता लगाने के लिए कहा था।
- इस बीच, डेमोक्रेटिक सांसद इस बात की जाँच की माँग कर रहे हैं कि सुरक्षित सरकारी चैनलों के बजाय व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मैसेजिंग ऐप पर अत्यधिक संवेदनशील जानकारी पर चर्चा क्यों की जा रही थी।

पर्यावरण मंत्रालय ने 2024-25 में प्रदूषण नियंत्रण कोष के 858 करोड़ रुपये का 1% से भी कम खर्च किया:

चर्चा में क्यों है?

- 25 मार्च को संसद में पेश संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 'प्रदूषण नियंत्रण' योजना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवंटित 858 करोड़ रुपये में से अब तक केवल 1 प्रतिशत से भी कम का उपयोग किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि संसदीय निगरानी के एक भाग के रूप में, विभिन्न विभाग-संबंधी स्थायी समितियां बजटीय आबंटन के मुकाबले सरकारी मंत्रालयों के व्यय और प्रदर्शन की जांच करती हैं तथा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

पर्यावरण पर संसदीय समिति के रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर विभाग से संबंधित स्थायी समिति ने अनुदान मांगों (2025-26) की रिपोर्ट में अपना आश्चर्य

व्यक्त किया और पर्यावरण मंत्रालय से "आत्मनिरीक्षण" करने और सकल कम उपयोग के कारणों पर गंभीरता से ध्यान देने को कहा।

- ध्यातव्य है कि 2024-25 में प्रदूषण नियंत्रण कोष के लिए 858 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन में से 21 जनवरी तक केवल 7.22 करोड़ रुपये के व्यय पर संसदीय समिति के आश्चर्य के जवाब में, पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इस योजना को जारी रखने के लिए 'अनुमोदन की प्रतीक्षा' के कारण धन का उपयोग नहीं किया जा सका। वहीं इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में मंत्रालय ने इस योजना के लिए आवंटित सभी बजट खर्च कर दिए हैं।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार इस योजना को पूरी तरह से वित्तपोषित करती है और यह केंद्र के प्रमुख 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)' के प्रमुख स्रोतों में से एक है, जिसने 2026 तक देश भर के 131 शहरों में पार्टिकुलेट मैटर 10 (सूक्ष्म प्रदूषक) प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) क्या है?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया था, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को शामिल करके 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर 10 (PM10) सांद्रता के लिए 40% तक की कमी या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की उपलब्धि हासिल करना है।

NCAP का उद्देश्य:

- 2024 तक PM10 सांद्रता में 20-30% की कमी लाना
- 2026 तक PM10 सांद्रता में 40% की कमी लाना
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना
- 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना

NCAP में हुई प्रगति:

- 2023-24 में, 131 में से 95 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार दिखा
- 18 शहरों ने 2023-24 में PM10 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAQS) को पूरा किया
- प्रदूषण में 76.4% की कमी के साथ वाराणसी सबसे आगे रहा, उसके बाद मुरादाबाद (58%) और कानपुर (51.2%) का स्थान रहा

NCAP की चुनौतियाँ:

- आवंटित निधियों का कम उपयोग

- कार्यक्षमता, पारदर्शिता और सूचना की सार्वजनिक उपलब्धता का अभाव

संसदीय समिति द्वारा जलवायु परिवर्तन से जुड़े अन्य सुझाव:

- जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर, हाउस पैनल ने वैश्विक जलवायु प्रयासों और जलवायु निधि से अमेरिकी प्रशासन के पीछे हटने पर चिंता व्यक्त की। इसने कहा कि भारत, एक बड़ा देश होने के नाते, बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
- इस समिति ने 'हीट वेव' को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की हीट एक्शन कार्यक्रमों (HAP) को तैयार करने और लागू करने की भी सिफारिश की, और आगामी और अगली गर्मियों में औसत से अधिक तापमान वृद्धि की उम्मीद पर चिंता व्यक्त की।
- हाउस पैनल ने राष्ट्रीय तटीय मिशन के तहत निधियों की समग्र योजना और निष्पादन की भी सिफारिश की, क्योंकि पिछले दो वित्तीय वर्षों में इसके लिए निधियों में कटौती की गई थी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे 'रूस-यूक्रेन काला सागर सुरक्षा समझौते' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. रूस और यूक्रेन ने इसके तहत काला सागर में नौवहन और एक दूसरे के ऊर्जा अवसंरचना पर सैन्य हमलों को रोकने के लिए एक समझौता किया है।
2. यह समझौता का आधार जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र समर्थित 'काला सागर अनाज पहल' रहा है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)

2. हाल ही में खबरों में रहे 'काला सागर' को अटलांटिक महासागर का 'सीमांत सागर' माना जाता है। निम्नलिखित सागरों की सूची में से कौन-सा अटलांटिक महासागर का 'सीमांत सागर' **नहीं** है?

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

(a) बाल्टिक सागर

(b) लाल सागर

(c) मेक्सिको की खाड़ी

(d) भूमध्य सागर

Ans:(b)

3. चर्चा में रहे मैसेजिंग ऐप 'सिग्नल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह केवल टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए एक एन्क्रिप्टेड सेवा है, और यह फोन और वीडियो कॉल को संभाल नहीं सकता है।
2. इसके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की वजह से अमेरिका में सरकारी कर्मियों के लिए इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(d)

4. हाल ही में चर्चा में रही संसद की विभिन्न 'विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) संसद की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की कुल संख्या 27 है।

(b) इनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आते हैं।

(c) इनमें से प्रत्येक समिति में 21 सदस्य होते हैं - 14 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से।

(d) उपर्युक्त सभी सही कथन है।

Ans:(b)

5. चर्चा में रहे 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी, 2019 में इस कार्यक्रम को शुरू किया था।
2. इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक वायु में पार्टिकुलेट मैटर 10 की सांद्रता में 80 प्रतिशत तक की कमी करना है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(a)